www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

* Vol-2* *Issue-2* *February 2025*

आधुनिक भारत के बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल

रोहित

गेस्ट फैकल्टी, श्यामा प्रसाद मुख़र्जी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ़ दिल्ली

आजादी के बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का आजाद भारत की बुनियाद रखने में महत्वपूर्ण योगदान था। आज हम जिस अखंड भारत की बात करते है वो सिर्फ और सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही है। जब भारत आजाद हुआ था तब अग्रेजो ने भारत को दो हिस्सो में बांट दिया था जिससे लोगो मे अराजकता फैल गई थी तब हिन्दू और मुस्लिम दोनो पक्षो में खून–खराबा और लूटमार होने लगी जिस को रोकने का काम गांधी जी ने सरदार पटेल को दिया था, इसमे सरदार पटेल सफल भी हुए। स्वंतत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री और (लौहा पुरूष) की उपाधि प्राप्त, सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के एक प्रमुख सदस्य थे। पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वंतत्रता आन्दोलन में उन्होने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन में भारत की महानता और एकता ही उनका मार्गदर्शक रही।

स्वतंत्रता के दौरानभारत के समक्ष चुनौतिया

क्योंकि जब भारत आजाद हुआ उस में भारत मे 562 प्रिसंली स्टेट थे। सबसे बडा प्रश्न था कि इन प्रिसंली स्टेट का भारत में विलय कैसे होगा? मसलन इन रजवाड़ो के न सिर्फ शासक अलग थे बल्कि उनका झंड़ा भी अलग–अलग था। इन अलग अलग झंड़ो को तिंरगे मे कैसे शामिल किया जाए यह एक बड़ी चुनौती थी? मसलन कैसे हम एक समंतवादी औपनिवेशिक समाज को विकसित राष्ट्र के रूप में सांविधान के साथ आगें बढाएगे? इतने ज्यादा विविधता मूलक थे कैसे एक राष्ट्र बनाएगें? स्वतत्रता के समय भारत के समाने ऐसी कई चुनौतियँ थी जिन्हे न सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हल किया बल्कि भविष्य में ऐसी चुनौतिया न आए इसके लिए भी मजबूत उपाए भी करके गए।

देशी रियासतों का विलय और सरदार वल्लभ भाई पटेलः

भारत छोड़ो आन्दोंलन और फिर नौसैनिक विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार की स्थिति भारत में काफी कमजोर हो गई थी, अब लगभग यह तय हो गया था कि ब्रिटिश ज्यादा समय और भारत में नही रहेगें! कैबिनेट मिशन के अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार को भारत विभाजन को लेकर असहमति थी किन्तु एक बात अब तय थी कि ब्रिटिश भारत से जाने वाले है। अब भारतीय राष्ट्रवादियो को यह चिंता हो रही थी कि सरकार अपना रूख स्पष्ट करें कि, वह देशी रजवाड़ो के लिए कौन सा रूख अपनाने जा रही है क्योंकि भारत में 562 से ज्यादा देशी रियासते थी जिनमें से कुछ पाकिस्तान मे थी। इस समय भारतीय राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार की नैतिक जिम्मेदारी देखना चाहते थे कि वह राष्ट्र निर्माण मे भारत का साथ कहा तक देगीं। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ पीछे कर लिए, उन्होनें कहा कि हम प्रिंसली स्टेट के, बारे मे कोई राय नही दे सकते। भारत और पाकिस्तान यह खुद तय करे, बल्कि रियासते स्वयं तय करे कि उन्हे स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना है या भारत और पाकिस्तान मे मिलना है। मांउट एटली घोषणा मे भी यह बात स्पष्ट हो गई थी कि ब्रिटिश भारत से जाने वाले है। 3 जून 1948 को ब्रिटिश भारत को खाली कर देगे लेकिन उन्होने अभी तक भी प्रिसलीं स्टेट पर अपना रूख स्पष्ट नही किया था, कि भावी भारत का स्वरूप कैसा होगा उसकी कोई स्पष्ट रूपरेखा नही थी।

लाड़ लुई मांउट माउटबेटन ने 3 जून 1947 की धोषणा की, इसमे भी उन्होने अपना रूख स्पष्ट नही किया

बस उन्होनें देशी रियासतो से अपील की, कि उन्हे खुशी होगी अगर देशी रियासते अपना विलय करती है।

तत्कालीन समय में हमारे लीडर जैसे पंडित नेहरू के पास बहुत कार्यक्रम थे, प्रिसली स्टेट पर उनका रूख स्पष्ट नही था। वल्लभभाई पटेल स्वतंत्रता के बाद मात्र 2 वर्ष तक जीवित रहे लेकिन इतना बड़ा काम भारत के लिए करके गए।

"क्योकि नेहरू का काम उसके बाद ही शुरू होता है जहां पर पटेल का समाप्त होता"

1947 में हमारे समाने सबसे बड़ी चुनौती थी कि अखंण्ड भारत का निर्माण कैसे हो? क्योकि अगर नही होगा तो हमारी सारी योजनाए अधूरी रह सकती थी। मसलन उस समय भारत में 562 से ज्यादा देशी रियासते थी और तत्कालीन समय शीतयुद्व का था। अगर देशी रियासतो में से एक या दो में भी रियासतों में अमेरिका या रूस अपने सैनिक अडडे बना लेते तो उस स्थिति हम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते इसलिए देशी रियासतो के विलय को हम हलके में नही ले सकते थे।

वल्लभ भाई पटेल की हार्डकोर डिप्लोमेसी

संवैधानिक असेम्बली में ही सरदार पटेल ने शुरूआत मे अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि वह देशी रियासतो को लेकर काफी गम्भीर है। और देशी रियासतो की स्वतत्रंता को स्वीकार नही किया जाएगा। उस समय ब्रिटिश कांउसलर पटेल के साथ डील कर रहे थे तब यह तय हुआ कि 15 अगस्त 1947, भारत को आजादी मिलेगी तब उस समय क्या होगां। अगर देशी रियासतो का भारत मे विलय नही हुआ, तो यह देशी रियासते अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना लेगी। तब स्थिति और ज्यादा प्रतिकूल बन जाएगी। इसलिए 15 अगस्त 1947 से पहले हम एक तरीका विभाजित करते है। तब गृहमंत्री के पद पर सरदार पटेल थे। तब अतंरिम सरकार में फिर एक अलग विभाग जुलाई 1947 में बनाया गया उसका नाम था स्टेट डिर्पाटमेन्ट जिसके प्रमुख सरदार पटेल थे और उनके सचिव थे वी पी मेनन, इन दोनों ने मिलकर तब वो कूटनीति शुरू की जिससे देशी रियासतो का भारत मे विलय हो सका। वल्लभ भाई पटेल ब्रिटिश काउंसलर से बात करके `जंदम `जपसस ंहतमउमदज लेकर आए यह इसलिए लाया गया था क्योंकि जब 1947 के बाद भारत स्वतंत्र हो जाएगा और अगर ऐसी स्थिति में देशी रियासतो अपने स्वतत्रं अस्तित्व को बनाए रखने पर बल देगी तो उनकी स्वतत्रं विदेश नीति भी होगी जो अखंण्ड भारत की राह मे एक रूकावट बन सकती है इसलिए stane still agrement के अन्तर्गत सरदार पटेल ने सिर्फ तीन विषय जैसे रक्षा, संचार, विदेश, विषय देशी रियासतो लेने का प्रस्ताव किया। सरदार पटेल ने उन्हें समझाया कि पहले भी यह तीन विषय अपके पास नही थे। इनका प्रयोग पहले ब्रिटिश सरकार के माध्यम से किया जा रहा था और आप उनका सहयोग कर रहे थे। इसलिए हम आपसे बस सिर्फ यह तीन विषय मांग रहे है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पहले बात stane still agreement पर हुई और बहुत सारी रियासतो को राजी किया गया कि आप पहले इस पर हस्ताक्षर करे। तब इससे पहले ही सरदार पटेल ने Instrument of EÛsesion कि रूपरेखा तैयार कर ली उन्होने रियासतो को कहा आपको भारत का संविधान अपनाना ही पड़ेगा अथवा आपको भारत के साथ पूर्ण विलय करना पड़ेगा और इसके साथ उन्होंने प्रावधान भी किया कि जो विलय होगा वह पूर्ण और अतिम होगा मतलब आपके उत्तराधिकारी उसे स्वीकार करने से मना नही कर सकते, बदले में हम आपको बहुत सारी चीजें दे सकते है। जैसे–

प्रीविपर्स के रूप मे बड़ी रकम, आपकी पर्सनल प्रापर्टी पर इड़ियन गर्वमेंन्ट हाथ नही ड़ालेगी, और आप ने जो उपाधियाँ का प्रयोग किया है वो बना रहेगा और आपको इड़ियन यूनियन में एक सम्मान जनक पद दिया जाएगा मतलब राज्य प्रमुख या उप राज्य प्रमुख का प्रभार भी दिया जा सकता है। तब उड़ीसा के प्रिसं ने सरदार पटेल से वास्तविक स्थिति की जानकारी ली तो,सरदार पटेल ने कहा ''कि आप छोटी सी नदी मे छलांग लगा रहे है और में आपको पूरा समुद्व देना चाहता हूँ'' मतलब लोकतंत्र में आप भी चुनाव लड़ सकते है सरकार मे आ सकते है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल कूटनीति थी जिसे पुरस्कार की नीति कहा गया।

State still agreement के साथ Instrument of EÛsesion पर सब रियासतें एक के बाद एक हस्ताक्षर करते गए, कुछ रियासतो को छोड़कर बाकी सभी ने शांति पूर्ण से भारत मे विलय कर लिया। यह विश्व इतिहास में कोई छोटी बात नही थी क्योंकि यह पूरी प्रकिया बिना किसी के लहू को बहाए हुई थी। इसलिए इतिहास में पटेल के यह कार्य तुलना बिस्मार्क से की जाती है जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था किन्तु सरदार पटेल के द्वारा बिना रक्त बहाए गए किये गये एकीकरण के कारण वे इतिहास में बिस्मार्क से काफी आगे खड़े नजर

आते है।

वल्लभ भाई पटेल के बारें में कहा जाता है कि जितनी उन्होने मार्निग वाक की और डिनर खाए उतने किसी भी नेता नें नही खांए होगे। क्योंकि वो एक साथ 2 चीजों को डील कर रहे थे। एक तरफ वों देशी रियासतों के साथ डील कर रहें थे तो दूसरी तरफ वो संविधान सभा जो विश्व की सबसे ज्यादा बहुलवादी असंबेली थी। क्योकि संविधान सभा में जितने लोंग थे, जितने समूह थे, जितने विचार थे, जितनी पार्टिया थी, जितने दृष्टिकोण थे उनमे टकराहट होना स्वाभाविक था। उस इस स्थिति में पंडित जवाहर लाल नेहरू थोड़ा अनउपयुक्त थे क्योंकि नेहरू स्टेट फारवर्ड थे, बहुत महान नेता भी थे किन्तु थोड़ा शार्ट टेम्परर्ड भी थे। वो विरोध को सहन नही कर पाते थे।

कई बार तो संविधान असेंबली में मामला ऐसा फंस जाता था कि लगता अब बात बिगड़ने वाली है, लगता कि वार्ता यही टूट जाएगी, वो अमुख मेंम्बर नही मानेगा तब वल्लभ भाई पटेल बड़े प्यार से उस सदस्य के पास जाते जैसा कि रामचद्र गुहा ने बताया है और उस सदस्य के कंधे को थपथपाते हुए कहते कि कल सुबह

आप मेरे साथ मार्निग वॉक पर आएगे, फिर वो सदस्य सरदार पटेल के साथ मार्निग वॉक पर जाता, पता नही क्या बात होती कि दूसरे दिन जब वो सदस्य संविधान सभा मे आता तो बिलकुल शांत होकर बैठा रहते। उसी प्रकार से रात मे वो डिनर करते थे और डिनर देशी रियासतो के महाराजा के साथ नही, बल्कि वों डिनर करते थे, महाराजा के मिनिस्टर के साथ क्योंकि वो जानते थे कि महाराजा थोड़ा सकीर्ण और रूढिवादी है। हमारी बातो को आसानी से नही समझेगा। तो इसी लिए वो मंत्रियो के साथ डिनर करते और रात में इतनी भयानक पिचंर खीचते थें जिसको "पुरस्कार के साथ छड़ी की नीति भी कहा जाता है" जिसको वो जरूरी भी मानते थे क्योंकि state still agreement भी बहुत सारे स्टेट स्वीकार तो कर रहे थे किन्तु उससे आगे नही बढ रहे थे। मसलन Instrument of EÛsesion को टाल रहे थे। कई ने तो रिफ्यूज कर दिया था जैसे कश्मीर, जूनागढ, हैदराबाद, भोपाल और त्रावणकौर जैसी रियासतों ने इसे पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया था। इसके लिए सरदार पटेल ने एक तरीका बनाया हुआ था कि अब पुरस्कार की नीति तो बहुत हो गई, हमने आपको पुरस्कार दिया जैसे प्रिवीपर्स दिया, आपके टाइटल स्वीकार किए आपकी प्रापर्टी को मान्यता दी। इसके साथ ही आपको राज प्रमुख पद देने तक की बात भी की लेकिन अगर इसके बावजूद भी आप तैयार नही होते अर्थात् 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में विलय नही कर लेते तो फिर आपकी जनता आपके विरोध में खड़ी हो जाएगी और फिर हमारा दृष्टिकोण भी आपके प्रति कठोर हो जाएगा ये सरदार पटेल के पास एक ऐसी मजबूत छड़ी थी जिसने देशी रियासतो को हिला के रख दिया था। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 तक ज्यादातर रियासते भारत मे शामिल हो गई थी लेकिन कुछ रियासते आजादी के बाद भी उहापोह की स्थिति में थी अतं मे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ ने उन रियासतो को भी भारत मे विलय कर दिया। इस तरह हम कह सकते है कि भले भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी लेकिन वर्तमान भारत की नीव उस समय सरदार पटेल ने रखी थी।

त्रावनकोर

दक्षिण तटीय राज्य, त्रावनकोर उन प्रथम रियासतों में से एक था जिसने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। ऐसा कहा जाता है कि सी पी अय्यर (त्रावनकोर के दीवान) थे इन्होंने ब्रिटेन की सरकार के साथ गुप्त संधि कर ली थी क्योंकि ब्रिटेन की सरकार स्वतंत्र त्रावनकोर के पक्ष मे थी दरअसल इस क्षेत्र मे मोनोजाइट नामक खनिज काफी मात्रा में पाया जाता थां जो ब्रिटेन को नाभकीय हथियारों की दौड में बढ़त दिला सकता था। लेकिन केरल समाजवादी पार्टी के एक सदस्य ने अय्यर की हत्या का प्रयास किया तो सी पी अय्यर ने डर के कारण भारत से जुड़ने का फैसला किया और 30 जुलाई 1947 को त्रावनकोर भारत में शामिल हो गया।

जोधपुर

एक राजपूत रियासत थी जहा एक हिन्दू राजा था, अधिकाशं जनसंख्या हिन्दू थी, राजा असाधारण रूप से पाकिस्तान की ओर झुकाव रखता था। राजा धनवंत सिंह जो युवा और अनुभवहीन था यह अनुमान लगा रहा था कि पाकिस्तान के साथ उसकी रियासत की सीमा लगती है तो वह पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे तरीके से सौदेबाजी कर सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने महाराजा को अपनी मांगो को सूचीबद्व करने के लिये एक

हस्ताक्षर रहित खाली पेपर दे दिया था। इन्होने सैन्य एवं कृषकों की सहायता के निर्माण और आयात के लिये बदरगाह तक मुफ्त पहुँच का प्रस्ताव भी रखा। इस स्थिति को देखते हुए पटेल ने तुरत एक्शन लिया और प्रतिक्रिया स्वरूप राजा से सम्पर्क किया और उसे पर्याप्त लाभों एवं प्रस्तावो का आश्वासन दिया, सरदार पटेल ने आश्वासन दिया कि हथियारों के आयात की अनुमति होगी। जोधपुर को काठियावाड़ से रेल के माध्यम से जोड़ा जाएगा साथ ही अकाल के दौरान अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस तरह 11 अगस्त 1947 को महाराजा हनवंत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया।

भोपाल

1926 मे भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह खान थे. वह अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षित थें। नवाब हमीदुल्ला दो बार 1931 और 1944 में चेम्बर आफ प्रिसेस के चासंलर बने थे तथा भारत विभाजन के समय भी वह चांसलर थें आजादी का मसौदा घोषित होने के साथ ही उन्होने 1947 मे चांसलर पद से इस्तीफा दे दिया। नवाब हमीदुल्लाह मोहम्मद अली जिन्ना के मित्र थे। 14 अगस्त 1947 तक उन्होने कोई फैसला नही लिया। जिन्ना ने उन्हे पाकिस्तान मे सेक्रेटरी जनरल का पद देकर वहा आने का न्यौता दिया, तब उन्होने अपनी बेटी आबिदा को भोपाल रियासत का शासक बन जाने को कहा लेकिन आबिदा ने इससे इनकार कर दिया। मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल के स्वतत्रं रहने की घोषणा कर दी। 23 जनवरी 1949 को डा शंकर दयाल शर्मा को आठ माह के लिए जेल भेज दिया गया। इसी बीच सरदार पटेल ने सख्त रवैया अपनाकर नवाब के पास संदेश भेजा कि भोपाल स्वतंत्र नही रह सकता, भोपाल को मध्यभारत का हिस्सा बनना ही होगा। 29 जनवरी 1949 को नवाब ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त करते हुए सता के सारे अधिकार अपने हाथ मेले लिए जिसके कारण तीन महीने खूब आन्दोंलन हुआ। अततः नवाब हमीदुल्ला हर तरफ से हार गया, और उसने 30 अप्रैल 1949 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। सरदार पटेल ने नवाब को लिखे पत्र में कहा मेरे लिए ये एक बडी निराशाजनक और दुख की बात थी कि आपके अविवादित हुनर तथा क्षमताओ को आपने देश के उपयोग मे उस समय नही आने दिया जब देश को उसकी जरूरत थी। अतंतः 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत का हिस्सा बन गई।

हैदराबाद

हैदराबाद राज्य काफी साधन सपंन्न था. इसके उत्तर मे मध्य प्रांत, पश्चिम मे बाम्बे और दक्षिण और पूर्व मे मद्रास प्रांत था. यह सभी रियासतों में सबसे बड़ी एवं सबसे समृद्वशाली रियासत थी, जो दक्कन पठार के अधिकाशं भाग को कवर करती थी।

इस रियासतमें 85 प्रतिशत हिन्दू थे पर सेना और शासन में मुसलमानो का दबदबा था. हैदराबाद का नवाबनिजाम मीर उस्मान अली उस समय दुनिया के सबसे बड़े अमीरो मे शमिल था।इसने एक स्वतत्रं राज्य की मांग की एवं भारत में शामिल होने से मना कर दिया। इसने जिन्ना से मदद का आश्वासन प्राप्त किया और इस प्रकार हैदराबाद को लेकर कशमकश एवं उलझनें समय के साथ बढती गई।

पटेल एवं अन्य मध्यस्थों के निवेदनों एवं धमकिया निजाम के मानस पर कोई फर्क नहीं डाल सकी और उसने लगातार यूरोप से हथियारों के आयात को जारी रखा। परिस्थितियॉ तब भयावह हो गई, जब सशस्त्र कटटरपंथियो ने हैदराबार की हिंदू प्रजा के खिलाफ़ हिसक वारदातें शुरू कर दी। 13 सितंबर, 1948 के "आपरेशन पोलों" के तहत भारतीय सैनिको को हैदराबाद भेजा गया। 4 दिन तक चले सशस्त्र संघर्ष के बाद अंततः हैदराबाद भारत का अभिन्न अगं बन गया। बाद मे निजाम के आत्मसमर्पण पर उसे पुरस्कृत करते हुए हैदराबार राज्य का गर्वनर बनाया गया।

जूनागढ

जूनागढ पश्चिम भारत के सौराष्ट इलाके का एक बडा राज्य था। वहां के नवाब महावत खान की रियासत का ज्यादातर हिस्सा हिन्दुओ का था। जिन्ना और मुस्लिम लीग के इशारों पर जूनागढ के दीवान अल्लाहबख्श के अपदस्थ करके बेनजीर भुटटो के दादा शाहनवाज़ भुटटो को वहां का दीवान बनाया गया था। गुहा अपनी किताब मे लिखते है कि जिन्ना का जूनागढ को लेने का कोई इरादा नहीं था। वे नेहरू के साथ जूनागढ के बहाने कश्मीर की सौदेबाजी करना चाहते थे। भुटटो ने महावत खान पर दवाब बनाया किवह पाकिस्तान में विलय कर ले, 14 अगस्त, 1947 को महावत खान ने जूनागढ के पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया. एक

महीने बाद जब पाकिस्तान ने भी इसे स्वीकार कर लिया, तब सरदार पटेल उखड गए। उन्होनें जूनागढ के दो बडे प्रात मांगरोल और बाबरियावाड पर ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह के नेतृत्व मे सेना भेजकर कब्जा कर लिया.

महावत खान ने काफी कोशिश की पर जूनागढ की जनता ने उसका साथ नही दिया। इसी बीच कूटनीति का सहारा लेते हुए वीपी मेनन भुटटो से मिले और उन्हे समझाया कि जूनागढ की भौगोलिकता और हिन्दुओ की बहुलता होने की वजह से उसका पाकिस्तान में विलय कतई तर्कसंगत नही है, भुटटो ने भी दबी जबान मे इसे स्वीकार किया और मेनन को जनमत संग्रह कराने का भरोसा दिलाया। पर यह सिर्फ कोरा भरोसा ही था. इसी दौरान गांधीजी के पोते, समलदास गांधी की अगंवाई मे बॉम्बे मे जूनागढ की अंतरिम सरकार बनी, इस सरकार ने जनता के साथ मिलकार और महावत खान के विरूद्व जाकर भारत मे विलय के आंन्दोलन को हवा दी इस सबक पीछे सरदार पटेल की कूटनीति ही काम कर रही थी, बढते आंदोलन को देखकर नवाब महावत खान कराची भाग गया, आखिरकार नंवबर 1947 के पहले सप्ताह में शाहनवाज भुटटो ने जूनागढ के पाकिस्तान मे विलय को खारिज कर उसके हिन्दुस्तान मे विलय की घोषणा कर दी। इसी महीने यानी नवंबर मे भारतीय फौज ने जूनागढ पर कब्जा कर लिया, वीपी मेनन और पटेल के इस फैसले से माउंटबेटन नाराज हो गए। इसके बाद पटेल ने उनको खुश करने के लिए जूनागढ मे जनमत संग्रह करवाया जिसमे 90 फीसदी से ज्यादा जनता ने भारत मे विलय को स्वीकार किया इस तरह से 20 फरवरी 1948 को जूनागढ देश का हिस्सा बन गया।

लक्षद्वीप में कैसे फहराय तिंरगा

लक्षद्वीप को भारत में मिलाने में भी सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहां के लोगों को भारत के स्वतंत्र होने की सूचना 15 अगस्त 1947 के कई दिनों बाद मिली थी। पाकिस्तान से काफी दूर होने के बावजूद भी वह भारत के इस हिस्से पर दावा कर सकता था। तब पाकिस्तानी नौसेना के जहाज लक्षद्वीप के आस–पास मंड़राते हुए देखे भी गए थें लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान इस हिस्से पर अपना ध्वज फहराता सरदार पटेल ने होशियारी से काम लेते हुए लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का एक जहाज तिरंगा फहराने के लिए भेज दिया। भारतीय नौसेना ने समय रहते द्वीप पर भारत का राष्टीय ध्वज फहरा दिया। पाकिस्तानी नौसेना ने जब लक्षद्वीप पर भारतीय झंडा देखा तो निराश होकर वापस लौट गई और लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बन गया

संदर्भ–

1. मौलाना अबुल कलाम आजाद India Wins Freedom, में प्रकाशित।
2. राजमोहन गांधी, Patel, Life, 1991 1991 मे प्रकाशित।
3. दुर्गादास, India From Curzon to Nehru and After 1969 में प्रकाशित।
4. Brecher, Nehru, Political Biography, 1959 में प्रकाशित।
5. स्वराज में सी गोपालचारी का लेख।

Cite this Article-

रोहित, "आधुनिक भारत के बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल", Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:02, February 2025.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/
DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i2005
Published Date- 08 February 2025